प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील संख्या 495/2024

निर्णय सुरक्षित किया गया :--05.03.2024

निर्णय पारित किया गया :-- 17.06.2025

---

1. श्रीमती. रेखा गुप्ता पति विजय गुप्ता उम्र लगभग 46 वर्ष निवासी काली वार्ड कवर्धा, पुलिस थाना एवं तहसील–कवर्धा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

---अपीलकर्त्ता

बनाम

1. बलराम चंद्रवंशी पिता स्व. लहरीराम चंद्रवंशी उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी ग्राम सैहामालगी, थाना कुंडा, चौकी–दामापुर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता हेतु : श्री आकाश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : के लिए: सुश्री शर्मिला सिंघल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री कंचन कलवानी, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

(सीएवी निर्णय)

1. अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(4) के अंतर्गत वर्तमान दोषमुक्ति अपील विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला – कबीरधाम, कवर्धा (छ.ग.) द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 143/2020 में पारित दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक अ/1) के आदेश के विरुद्ध दायर की है, जिसके द्वारा विद्वान दंडाधिकारी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में "एनआई अधिनियम, 1881") की धारा 138 के अंतर्गत दायर परिवाद को खारिज कर दिया था और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:--

(क) परिवादी का यह प्रकरण है कि अभियुक्त तथा परिवादी एक–दूसरे को जानते हैं और अच्छे संबंधों के कारण, अभियुक्त ने अपीलकर्ता से अपनी घरेलू ज़रूरतों के लिए 22,00,000/– रुपये का ऋण लिया है। परिवादी का यह भी प्रकरण है कि अपने ऋण और दायित्व का भुगतान करने के लिए, अभियुक्त ने यूनियन बैंक, शाखा कवर्धा से दिनांक 08.07.2019 को जारी संख्या 033953 और 834043 के दो चेक क्रमशः 12,00,000/– रुपये और 10,00,000/– रुपये के दिए हैं।

(ख) 12,00,000/– रुपये का जारी किया गया उक्त चेक, 31.08.2019 को परिवादी द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा कवर्धा में खोले गए खाते में जमा किया गया था। उक्त चेक 02.09.2019 को एक ज्ञापन के माध्यम से इस पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया गया कि "अस्वीकृत होने के कारण खाता बंद कर दिया गया है"। इसके बाद, अपीलकर्ता ने 01.10.2019 को अभियुक्त को एक विधिक नोटिस भेजा, उक्त नोटिस अभियुक्त को 09.10.2019 को प्राप्त हुआ, लेकिन न तो अपीलकर्ता को राशि का भुगतान किया गया और न ही अभियुक्त ने उक्त नोटिस का उत्तर दिया, जिसके कारण परिवादी को अभियुक्त के विरुद्ध एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला – कबीरधाम, कवर्धा (छ.ग.) के समक्ष परिवाद दर्ज करानी पड़ी।

3. परिवादी ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 145 के तहत दिए गए शपथ पत्र के माध्यम से स्वयं का परीक्षण किया है,जिसमें उसने परिवाद में अपनाए गए रुख को दोहराया है और अपने परिवाद के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं, अर्थात चेक संख्या 033953 दिनांक 08.07.2019 (प्रदर्श पी/1), चेक वापसी ज्ञापन दिनांक 02.09.2019(प्रदर्श पी/2), विधिक नोटिस दिनांक 01.10.2019 (प्रदर्श पी/3), डाक रसीद (प्रदर्श पी/4), डाक वितरण (प्रदर्श पी/5)। साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह 2014 से सरकारी नौकरी में है और डिस्पैच क्लर्क के पद पर कार्यरत है और उसे 10,000 रुपये वेतन मिलता है। उसके दो बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और उसका वार्षिक खर्च लगभग 1,50,000 रुपये है उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी को 2017 से जानती है और उसे याद नहीं है कि उसने 12,00,000 रुपये कब लिए थे। उसने बताया है कि अभियुक्त ने अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए तीन किश्तों में 12,00,000 रुपये लिए थे और वर्ष 2018 में अभियुक्त ने उसकी पुत्री के विवाह के लिए 10,00,000 रुपये लिए थे। उसने बताया है कि वर्ष 2017 में यह राशि किसी अधिवक्ता के कार्यालय में अभियुक्त को दी गई थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि 06.11.2019 को आरोपी ने उसके बैंक खाते में 2,00,000 रुपये जमा किए थे और इस बात से इनकार किया कि ब्याज भी दिया गया है। उसने स्वीकार किया है कि उसने यह राशि जमानत के तौर पर ली थी।उसने कंडिका 22 में स्वीकार किया है कि उसके पिता ने बिलासपुर स्थित संपत्ति 70,00,000–75,00,000 रुपये के विक्रय मूल्य पर बेची है, जिसमें से उसके पिता ने 25,00,000 रुपये दिए हैं, लेकिन उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियुक्त ने किसी साक्षी से परीक्षा नहीं की है, लेकिन उसने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की है, जिसमें उसने आरोपों से इनकार किया है और अवैध मांग के आधार पर झूठे आरोप लगाने की तर्क दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के तहत परिवाद को खारिज कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवाद को खारिज करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि कोई बैंक स्टेटमेंट या भुगतान की रसीद अभिलेख में नहीं रखी गई है, इसलिए परिवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त ने किसी ऋण या देनदारी के लिए चेक दिए हैं, इसलिए परिवाद को खारिज कर दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्त करने के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में विफल रही है और उसने अभियुक्त को गलत तरीके से दोषमुक्त कर दिया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ की हैं कि अपीलकर्ता एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तत्वों को साबित करने में असमर्थ है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में उद्धृत

विधिक दृष्टांत द्वारा शामिल किए गए वर्तमान मामले की गलत व्याख्या की है और तर्क दिया कि एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 का प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि आंशिक भुगतान चेक बैंक में जमा होने के बाद किया गया था, इसलिए चेक पर कोई पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि चेक 31.08.2019 को बैंक में भुनाने के लिए जमा किया गया था और आंशिक भुगतान 06.11.2019 को किया गया था क्योंकि परिवादी को चेक पर पृष्ठांकन करने का कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए, आक्षेपित आदेश
रद्द किए जाने योग्य है और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि परिवादी ने यह दर्शाने के लिए कोई अभिलेख पेश नहीं किया है कि उक्त चेक अभियुक्त द्वारा किसी ऋण या देनदारी के लिए दिए गए थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक चेक 31.08.2019 को प्रस्तुत किया गया था और वह 2.09.2019 को अनादरित हो गया और अभियुक्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जो कि एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि परिवादी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने अभियुक्त को पैसे दिए हैं, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करने वाली विकृत या अवैधता से ग्रस्त नहीं है और वे अपील को खारिज करने का अनुरोध करते है ।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

8. पक्षों के प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण हेतु यह विवाद्यक उभर कर आया है:--

"क्या विद्वान विचारण न्यायालय **द्वारा 11.01.2023 के आदेश द्वारा परिवाद को खारिज करना न्यायोचित था,जिसमें एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 56 के प्रावधान लागू थे?"**

9. इस न्यायालय द्वारा उठाए गए विवाद्यक का निर्धारण करने के लिए, इस न्यायालय के लिए एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 56 का उद्धरण देना और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का भी अध्ययन करना समीचीन है। एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 56 इस प्रकार है:--

"धारा 56. देय राशि के भाग के लिए पृष्ठांकन--

किसी परक्राम्य लिखत पर कोई भी लेख बातचीत के प्रयोजन के लिए वैध नहीं है यदि ऐसा लेख उस लिखत पर देय प्रतीत होने वाली राशि के केवल एक भाग को स्थानांतरित करने का दावा करता है; परंतु जहां ऐसी राशि आंशिक रूप से चुकाई गई है, वहां इस आशय का एक नोट लिखत पर पृष्ठांकित किया जा सकता है, जिस पर तब शेष राशि के लिए बातचीत की जा सकती है।"

10. परिवादी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने 06.11.2019 को 2,00,000/- रुपये की राशि विजया बैंक में उसके खाते में जमा की थी जिसका अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया चेक उसने 31.08.2019 को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया था और 01.10.2019 को नोटिस भेजा था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा राशि परिवादी द्वारा चेक जमा करने और नोटिस भेजने के बाद जमा की गई थी, इसलिए,परिवादी के लिए एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के तहत देय राशि के कुछ हिस्से के लिए समर्थन करने का कोई अवसर नहीं था।विद्वान विचारण न्यायालय **ने दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल बनाम हितेश महेंद्रभाई पटेल एवं अन्य, जो 2023 (1) एससीसी 578 में रिपोर्ट किया गया था,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को गलत तरीके से लागू किया है, बिना एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के प्रावधानों और मामले के तथ्यों पर विचार किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, यह निष्कर्ष अवैध और विधि के विपरीत है। दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के प्रावधानों पर विचार किया है और निम्नलिखित निर्णय दिया है:--

"13. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब उत्तर-दिनांकित चेक जारी करने के बाद आंशिक भुगतान किया जाता है, तो भुनाने के समय विधिक रूप से लागू ऋण चेक में दर्शाई गई राशि से कम होता है। आंशिक भुगतान या पूर्ण भुगतान ऋण अर्जित होने की तिथि से लेकर चेक भुनाने की तिथि के बीच किया जा सकता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम उत्तर-दिनांकित चेक जारी करने और सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किए गए चेकों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का संदर्भ लें।

14. इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह विवाद्यक था कि क्या उत्तर-दिनांकित चेकों का अनादर, जो खरीदारों द्वारा 'अग्रिम भुगतान' के रूप में जारी किए गए थे, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आएंगे यदि क्रय आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया **गया कि धारा 138 केवल यह तब लागू होता है जब चेक जारी करने की तिथि पर कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण विद्यमान हो। सैम्पेली सत्यनारायण राव बनाम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड मामले में,उत्तरवादी ने एक विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए ऋण दिया और सुरक्षा के लिए उत्तर-दिनांकित चेक दिए गए। यह** अभिनिर्धारित किया **गया कि धारा 138 केवल यह तब लागू होता है जब चेक जारी करने की तिथि पर विधिक रूप से लागू करने योग्य ऋण विद्यमान हो। सैम्पेली सत्यनारायण राव बनाम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड मामले में, उत्तरवादी ने एक बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए ऋण दिया और सुरक्षा के लिए उत्तर-दिनांकित चेक दिए गए।चेक अस्वीकृत हो गए और धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज की गई। इंडस एयरवेज (सुप्रा) से अलग करते हुए, यह यह** अभिनिर्धारित किया **गया कि धारा 138 के लागू होने का परीक्षण यह है कि क्या चेक में उल्लिखित तिथि पर विधिक रूप से लागू करने योग्य ऋण था। यह** अभिनिर्धारित किया **गया कि यदि उत्तर सकारात्मक है, तो धारा 138 के प्रावधान लागू होंगे।**

15. श्रीपति सिंह बनाम झारखंड राज्य मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि यदि चेक सुरक्षा के रूप में जारी किया जाता है और यदि ऋण का भुगतान किसी अन्य रूप में नियत तिथि से पहले नहीं किया जाता है या यदि पक्षों के बीच पुनर्भुगतान स्थगित करने के लिए कोई सहमति या करार नहीं है, तो चेक प्रस्तुति के लिए परिपक्व होगा:

"21. किसी वित्तीय लेन-देन के तहत जमानत के तौर पर जारी किए गए चेक को हर परिस्थिति में बेकार कागज़ नहीं माना जा सकता है।'प्रतिभूति' अपने वास्तविक अर्थ में सुरक्षित होने की स्थिति है और ऋण के लिए दी गई प्रतिभूति, भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी गई राशि होती है। यह किसी दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दी, जमा या गिरवी रखी जाती है जिससे लेन-देन के पक्षकार बंधे होते हैं। यदि किसी लेन-देन में, ऋण दिया जाता है और उधारकर्ता एक निर्दिष्ट समय-सीमा में राशि चुकाने के लिए सहमत होता है और इस तरह के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में चेक जारी करता है; यदि ऋण राशि नियत तिथि से पहले किसी अन्य रूप में चुकाई नहीं जाती है या यदि पक्षों के बीच राशि के भुगतान को स्थगित करने के लिए कोई अन्य समझौता या समझौता नहीं होता है, तो प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया चेक प्रस्तुति के लिए परिपक्व हो जाएगा और चेक का आहर्ता उसे प्रस्तुत करने का हकदार होगा।ऐसी प्रस्तुति पर, यदि वह अस्वीकृत हो जाती है, तो धारा 138 और एन.आई. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत परिकल्पित परिणाम भुगतने होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जब कोई चेक जारी किया जाता है और उसे किसी राशि के पुनर्भुगतान के लिए 'सुरक्षा' के रूप में माना जाता है, जिसके पुनर्भुगतान के लिए एक समय अवधि निर्धारित की जाती है, तो यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा चेक, जो 'सुरक्षा' के रूप में जारी किया गया है, उस ऋण या पुनर्भुगतान की परिपक्व होने वाली किस्त से पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है जिसके लिए ऐसा चेक सुरक्षा के रूप में जारी किया गया है। इसके अलावा, उधारकर्ता के पास ऋण राशि या ऐसी वित्तीय देनदारी को किसी अन्य रूप में चुकाने का विकल्प होगा और इस प्रकार, यदि देय ऋण राशि सहमत अवधि के भीतर चुका दी जाती है, तो उसके बाद सुरक्षा के रूप में जारी किया गया चेक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऋण का पूर्व भुगतान या कोई परिवर्तित स्थिति जिसके कारण पक्षों के बीच करार हो, सुरक्षा के रूप में जारी किए गए चेक को प्रस्तुत न करने के लिए अनिवार्य शर्त है। ये केवल वे बचाव हैं जो एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में चेक जारी करने वाले के लिए उपलब्ध होंगे। इसलिए, ऐसा कोई कठोर नियम नहीं हो सकता कि सुरक्षा के रूप में जारी किया गया चेक, चेक के आहर्ता द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करार है, तो चेक को भी 'मांग पर वचन पत्र' में बदल दिया जाएगा और सभी परिस्थितियों में, राशि वसूलने के लिए यह केवल एक दीवानी मुकदमा होगा, जो कि विधि का उद्देश्य नहीं है। जब कोई चेक जारी किया जाता है भले ही वह 'सुरक्षा' के रूप में हो, उससे होने वाले परिणाम चेक जारीकर्ता को भी ज्ञात होते हैं और ऊपर बताई गई परिस्थिति में, यदि चेक प्रस्तुत किया जाता है और उसका अनादर हो जाता है, तो चेक धारक/आहर्ता के पास वसूली के लिए दीवानी कार्यवाही या दंड के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का विकल्प होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, मुकदमे की प्रकृति के संबंध में शर्तें तय करना चेक जारीकर्ता का काम नहीं है। (जोर दिया गया)..

16. पूर्व उदाहरणों के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

16.1. जहाँ उधारकर्ता एक निश्चित समय–सीमा के भीतर ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है और सुरक्षा के लिए चेक जारी करता है, लेकिन समय–सीमा के भीतर ऋण चुकाने में चूक करता है, तो चेक प्रस्तुति के लिए परिपक्व हो जाता है। जब देनदार द्वारा चेक को भुनाने की कोशिश की जाती है और वह अनादरित हो जाता है, तो अधिनियम की धारा 138 लागू होगी;

16.2. हालाँकि, जब चेक को सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है, तो मुख्य नियम यह है कि जिस दिनांक को चेक जारी किया जाता है और जिस दिनांक को चेक परिपक्व होता है, उसके बीच ऋण किसी अन्य माध्यम से चुकाया जा सकता है। केवल तभी जब ऋण देय तिथि के भीतर किसी अन्य माध्यम से नहीं चुकाया जाता है, चेक प्रस्तुति के लिए परिपक्व होगा।

16.3. यदि ऋण देय तिथि से पहले चुका दिया गया है या यदि कोई 'परिवर्तित स्थिति' है, तो चेक को भुनाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

11. अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **दशरथभाई त्रिकमभाई पटेल (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अतिरिक्त, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1506/2023 में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया है।श्री हिरानी एंटरप्राइजेज के मामले में **चिरागभाई रामभाई हिरानी बनाम गुजरात राज्य, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीआरएम संख्या 44212/2014, मेसर्स एम.बी. मेटल इंडस्ट्रीज बनाम मेसर्स विजय इम्पेक्स, केरल उच्च न्यायालय द्वारा शिजू के. बनाम नलिनी एवं अन्य** के मामले में, जो 2015 एससीसी ऑनलाइन केआर 36498 में रिपोर्ट किया गया था, और प्रस्तुत किया कि चूँकि चेक में पृष्ठांकन नहीं किया गया है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवाद को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि सभी मामलों में आंशिक भुगतान चेक बैंक में जमा करने से पहले या कुछ मामलों में नोटिस जारी होने से पहले ही कर दिया गया था, जबकि वर्तमान मामले में, 09.10.2019 को नोटिस प्राप्त होने के बाद, अभियुक्त ने 06.11.2019 को राशि जमा कर दी है, अतः परिवादी के लिए चेक या नोटिस में एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के तहत पृष्ठांकन करने का कोई कारण नहीं था। एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अवलोकन से भी, एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए, विधि की आवश्यकता यह है कि चेक उस दिनांक से 3 महीने के भीतर या उसकी वैधता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और चेक प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को लिखित में सूचना देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है और यदि चेक जारीकर्ता उक्त राशि का भुगतान प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, चेक धारक को, सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, करने में विफल रहता है। जबकि एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल दो आकस्मिकताएँ उपलब्ध हैं और चेक में पृष्ठांकन के लिए कोई अन्य आकस्मिकताएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके लिए अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता को आंशिक भुगतान की आवश्यकता हो।इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 56 के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू किया है, यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि चूँकि परिवाद दर्ज करने से पहले परिवादी द्वारा 2,00,000/– रुपये की राशि प्राप्त कर ली गई थी। अतः , एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि न्यायालय विधायिका के विवेक में कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं, विधायिका का मसौदा तैयार करते समय, न्यायालय केवल विधि की व्याख्या कर सकता है, इसलिए,आक्षेपित आदेश दिनांक 11.01.2023 अवैध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वैसे भी, परिवादी ने अपने परिवाद में कहा है कि अभियुक्त को मकान और ज़मीन खरीदने के लिए 22,00,000/– रुपये दिए गए हैं और उक्त ऋण चुकाने के लिए उसने 12,00,000/– रुपये का चेक दिया है और सीआरपीसी कि धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान में, उसने यह नहीं बताया है कि उसने किस ऋण के लिए 2,00,000/– रुपये का भुगतान किया है, हालाँकि ये तथ्य केवल आरोपी के ज्ञान में हैं, इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करके अवैधता की है कि परिवादी ने 2,00,000/– रुपये की रसीद का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए यह अभिनिर्धारित नही किया जा सकता कि ऐसा चेक ऋण या देयता के लिए दिया गया था। इस प्रकार, 11.01.2023 का आक्षेपित आदेश इस आधार पर अवैध है और यह इस अदालत द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

14. तथ्य, विषय पर विधि और पक्षों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि परिवादी ने यह साबित कर दिया है कि चेक ऋण या देयता के लिए दिया गया था, इसलिए, परिवाद को खारिज करने वाला विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश विकृत, अवैध और विवेकहीन है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियुक्त एन.आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उत्तरवादी/अभियुक्त को केवल 1,00,000 रुपये के जुर्माने का दंड पारित किया जाता है, जो चेक की राशि के अलावा है, जो अभियुक्त द्वारा देय 12,00,000 रुपये है। 1,00,000/– रुपये का जुर्माना परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देय है। चेक की राशि और क्षतिपूर्ति अभियुक्त द्वारा आज से आठ सप्ताह

के भीतर विचारण न्यायालय में जमा किया जाएगा, अन्यथा अभियुक्त को तीन महीने के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा ।

15. परिणामस्वरूप, दोषमुक्त करने की अपील स्वीकार की जाती है।

सही/–

नरेंद्र कुमार व्यास

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur